गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) वर्तमान में राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर हुए वित्तीय घपले का कोई मामला सामने नहीं आया है।

अयोध्या के आसपास अधिग्रहीत भूमि

1574. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयोध्या में विवादित स्थल के आस-पास कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित व्यक्तियों को मुआवजा देने को आधार बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और कब तक इस मुआवजे का भुगतान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :(क) केन्द्र सरकार द्वारा "अयोध्या में कतिपय भूमि अर्जन अधिनियम, 1993" के अधीन विवादित भूमि समेत अधिग्रहीत की गई कुल भूमि का क्षेत्रफल 112 बीघा, 02 बिस्वा. 13 बिस्वांसी है।

(ख) से (घ) अयोध्या में कतिपय भूमि अर्जन अधिनियम, 1993 की धारा 8 में उन भू-स्वामियों, जिनकी भूमि, इमारत, ढांचे अथवा अन्य सम्पत्ति इत्यादि केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, के दावों का निर्णय करने तथा उन्हें मुआवजे का भुगतान करने के लिए दावा आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान है। दावा आयुक्त ने पहले ही 68 मामलों में निर्णय ले लिया है तथा कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद इन मामलों में भुगतान किए जा रहे हैं। शेष मामले प्रौसेस करने के बाद दावा आयुक्त द्वारा उन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में अपराध

1575. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में जनवरी, से 31 मई, 1998 के दौरान हत्या, लूट और बलात्कार करने के बाद हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) उपरोक्त घटनाओं में से पुलिस थानों के आसपास तथा दिन-दहाड़े, कितनी हत्याएं हुई; और

(ग) हत्याओं और अन्य अपराधों के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनके लिए कितनों को सजा दी गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित स्थिति सूचित की है:—

शीर्ष	1.1.1998 से 31.5.1998 तक की अवधि के दौरान सूचित किए गए मामलों की संख्या
हत्या	268
लूटपाट	272
बलात्कार के बाद हत्या	1

प्रश्नाधीन अवधि के दौरान, पुलिस स्टेशनों के नजदीक दो हत्याएं की गईं और 32 हत्याऐं दिन दहाड़े हुई।

ऊपर उल्लिखित मामलों में कुल मिलाकर 628 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

इनमें से 144 का चालान किया गया और उन पर न्यायालयों में मुकद्मा चल रहा है।

वैधानिक विकास बोर्डों के लिए राज्यों को स्वीकृतियां

1576. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें वैधानिक विकास बोर्डों के गठन के लिए सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(ख) किन-किन राज्य सरकारों के वैधानिक विकास बोर्डों की स्थापना के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित और विचाराधीन है;

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को कितने प्रस्तावों को वापिस लौटाया जा चुका है; और

(घ) वैधानिक विकास बोर्डों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और क्या ये बोर्ड सीधे सरकार के नियंत्रणाधीन है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(2) में दो राज्यों, नामतः महाराष्ट्र और गुजरात में विकास बोर्डों की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है। महाराष्ट्र में विकास बोर्डों का गठन किया जा चुका है। गुजरात राज्य सरकार से कच्छ के लिए विकास बोर्ड स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा है।

विकास बोर्ड के संबंध में राज्यपालों की विशेष जिम्मेवारी है। ये विशेष जिम्मेवारियां (I) समग्र राज्य की

आवश्यकताओं के अध्याधीन ऐसे बोर्डों के क्षेत्रों के ऊपर विकासात्मक व्यय के लिए निधियों का न्यायसंगत आवंटन, और (II) तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उचित प्रबंध करना और उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में, राज्य की समग्र जरूरतों के मद्देनजर, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। प्रत्येक विकास बोर्ड के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष एक रिपोर्ट राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जानी अपेक्षित है।

Minorities in Police Forces

1577. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to ensure proper representation of minority community in terms of their numerical strength in various Central Police forces/establishments, including Delhi Police;

(b) if so, the details of the proposal *received/under consideration* and decision taken thereon;

(c) the present status of the proposal; and

(d) the fresh initiatives taken by Government for the welfare and economic uplift of members of minority communities in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) With a view of ensuring the all embracing character of the Central para Military Forces and providing adequate *representation to all regions* and communities, recruitment is organised in different parts of the country, after due publicity. As a part of this exercise, efforts are also made of ensure that eligible candidates from minority communities are aware of the employment opportunities available in the Central Para-Military Forces.

(d) The following schemes have been initiated to uplift the minority communities:—

(i) Schemes of Pre-examination *Coaching for weaker sections.*

(ii) Scheme of Multi Sectoral Development Plans to identify the requirements of credit, marketing, training and technological *support for activities persued by* Minorities in 41 minority concentration Districts.

(iii) Enhancement of equity share of the Central Government in the paid up Capital of National Minorities Development and Finance (NMDFC) Corporation from 25% to 60%.

Funds allocated to N.E. Council

1578. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the year-wise allocation of funds made to the North-Eastern Council under the 'plan' head during the period 1994—98;

(b) the names of the schemes for which these funds were provided alongwith the amounts of these funds;

(c) the names of the schemes for which these funds were actually spent during the above said period; and

(d) the details of the achievements obtained through the said spending.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Details are given in the Annexure (*See* Appendix 184, Annexure No 50)

(d) The major achievements are:—

Completion of Rokhia Gas based Power Project in Tripura; Completion of Doyang Transmission Scheme; Completion of 14 Inter-State roads; Completion of 7 roads of economic importance; Substantial progress in construction of Doyang and Ranganadi Hydro Electric Power Projects; Substantial progress in upgradation work in the following three NEC funded Health Institutes namely Dr. B. Barooah Cancer Institute, Guwahati, Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Regional Para Medical & Nursing Training Institute, Aizwal.